in the payment of wages are those which have been referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). The Government had constituted a Group of Ministers (GOM) to evolve a strategy for payment of statutory dues (including wages) to the employees of CPSUs. The GOM met on 29.8.97 but could not finalise a strategy on account of dissolution of the Parliament. The present Government is seized of the problem. In the union budget for 1998-99 a provision of Rs. 1482 crores has been made for non-plan loans to Public Sector Enterprises mainly for payment of salaries and wages to the employees of sick and convalescent PSUs.

देश में बाल मजदूर

2220. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) बाल मजदूरी रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में अब तक कानून के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज हुए हैं; क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यानारायण जटिया): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बच्चों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गयी है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाए जाने और जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने के लिए चूककर्ता नियोजकों से क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000/- रु० वसूल किए जाने का निदेश दिया था। सर्वेक्षण का पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया गया है। जोखिमकारी और गैर जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत पहचान किए गए बच्चों की संख्या क्रमशः 126665 और 428305 थी। समुचित सरकारें, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपबंधों को भी प्रवर्तित करती रही हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान चलाए गए अभियोजनाओं तथा प्राप्त सिद्धि दोषों की कुल संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	अभियोजनों की संख्या	सिद्धिदोषों की संख्या
1996-97	458	18
1997-98	676	29

(घ) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अधिकांश बच्चे चालू वर्ष के दौरान विशेष स्कूल की शिक्षा का अपना तीसरा वर्ष पूरा करेंगे।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य-वार वितरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कर्मकार
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,661,940
2.	असम	327,598
3.	बिहार	942,255
4.	गुजरात	523,585
5.	हरियाणा	109,691
6.	हिमाचल प्रदेश	56,438
7.	जम्मू एवं कश्मीर	**
8.	कर्नाटक	976,247
9.	केरल	34,800
10.	मध्य प्रदेश	1,352,563
11.	महाराष्ट्र	1,068,418
12.	मणिपुर	16,493
13.	मेघालय	34,633
14.	नागालैण्ड	16.476
15.	उड़ीसा	452,394
16.	पंजाब	142,868
17.	राजस्थान	774,199

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कर्मकार
18.	सिक्किम	5,598
19.	तमिलनाडु	578,889
20.	त्रिपुरा	16,478
21.	उत्तर प्रदेश	1,410,086
22.	प० बंगाल	711,691
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,265
24.	अरुणाचल प्रदेश	12,395
25.	चंडीगढ़	1,870
26.	दादर एवं नगर हवेली	4,416
27.	दिल्ली	27,351
28.	दमन एवं दीव	941
29.	गोवा	4,656
30.	लक्षद्वीप	34
31.	मिजोरम	16,411
32.	पांडिचेरी	2,680
	योग	11,285,349

** जनगणना नहीं करवायी जा सकी।

टिप्पणी: 1991 के लिए आंकड़े 5—14 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मकारों से संबंधित है।

Rehabilitation of Child Labour in Assam

2221. SHRIMATI BASANTI SARMA: **Will the Minister of LABOUR be pleased to state:**

(a) the details of grants provided by Government to the State Government of Assam under the Ninth Five Year Plan for the rehabilitation of child labour and terrorist affected persons and bonded labour;

(b) the details of child labour and bonded labour and terrorist affected persons identified during this Plan in the country, State-wise; and

(c) the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard;

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) no grants have been provided as yet to the State Government of Assam under the Ninth Five Year Plan for rehabilitation of child labour, bonded labour and terrorist affected persons. However, an amount of Rs. 25 crores was sanctioned to the State Government of Assam in 1996-97 under Non-Plan rehabilitation of people affected by ethnic violence.

(b) According to 1991 Census, the total number of working children in the country was 11,285,349. Recently first round of survey of working children was conducted on the direction of Supreme Court, during the course of which 5,54,970 children were found to be employed. The State-wise details are given in the Statement (*See below*)

In October 1996, the various State/ Union Territory Governments were advised to conduct sruvey to identify bonded labourers in their states latest by 31-12-96. The outcome of the survey as reported is given below:

1. Arunachal Pradesh	2460
2. Bihar	106
3. Karnataka	19
4. Madhya Pradesh	18
5. Maharashtra	02
6. Uttar Pradesh	237
7. Tamil Nadu	24918
	27760

No data is being maintained regarding terrorist affected persons.

(c) Government have taken a series of steps for the elimination of child labour working in hazardous occupations. Under the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, the employment of children is prohibited in 7 occupations and 18 processes contained in parts A and B of the schedule to the Act. There are also legal provisions in various other labour laws for safeguarding the interests of working children. Apart from legal